Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

पेपर – III || भाग – II

अर्थशास्त्र
और
कानून

SIERRA INNOVATIONS

vFk'kkL=

1.	vFk'kkL=	1
2.	पूंजी बाजार	4
3.	म्यूचुअल फंड	8
4.	स्टॉक एक्सचेंज	9
5.	राष्ट्रीय आय	10
6.	मुद्रास्फीति	13
7.	कम्पनी	18
8.	बैंकिग	21
9.	अनर्जक गैर निष्पादित सम्पति (**NPA**)	27
10.	वित्तीय समावेशन	37
11.	राजकोषीय नीति	44
12.	कर (**TAX**)	49
13.	जी.एस.टी. का इतिहास	53
14.	व्यापार नीति	57
15.	विनियम दर	65
16.	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन	68
17.	विश्व बैंक	71
18.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WTO**)	72
19.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	77
20.	वित्त आयोग	82
21.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	84
22.	ई–कॉमर्स	87
23.	बेरोजगारी	88
24.	गरीबी	89
25.	आर्थिक विकास	92
26.	पंचवर्षीय योजनाएं	98

27. राजस्थान में कृषि से जुडे प्रमुख तथ्य और वर्तमान दशा 100
28. राज्य में बागवानी 109
29. पशुपालन 112
30. औद्योगिक क्षेत्र 114
31. राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं 123

कानून

1. विधि की अवधारणा 139
2. कब्जा 142
3. वर्तमान विधिक मुद्दे 152
4. साइबर अपराध 163
5. बौद्धिक सम्पदा अधिकार 171
6. घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 180
7. बल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 185
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन निवारण निषेध एवं सुधार अधिनियम, 2013 188
9. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 196
10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1995 205

अर्थशास्त्र

Toppersnotes
Unleash the topper in you

vFk'kkL=

- प्राचीन समय में अर्थ शब्द का अभिप्राय धन से लिया जाता था ।
- किसी देश में होने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपनायी गई व्यवस्था, नियम, नीतियाँ उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है ।
- अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है-

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था :-

- यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों और सम्पत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का नियंत्रण हो तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है ।
- सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज कल्याण होता है ।
- इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता पायी जाती है । वस्तु और सेवाओं का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

2. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था :-

- इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर निजी व्यक्तियों/निजी क्षेत्रों का नियत्रंण होता है ।
- इस अर्थव्यवस्था में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है ।
- आर्थिक विषमता पायी जाती है ।
- वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है । (बाजार आधारित मूल्य निर्धारण)

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था :-

- इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद व पूंजीवाद दोनों के लक्षण पाये जाते है अर्थात उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों को अधिकार होता है ।
- सरकार द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है ।
- वस्तुओं की कीमतें बाजार आधारित होती है । लेकिन सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण किया जा सकता है ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है ।

उत्पादन के कारक :- उत्पादन के लिए चार कारक महत्वपूर्ण माने जाते है ।

क्र.सं.	उत्पादन के कारक	लागत
1.	भूमि	किराया
2.	पूंजी	ब्याज
3.	श्रम	मजदूरी
4.	उद्यम	लाभ

कारक लागत :-

- किराया + ब्याज + मजदूरी + लाभ
- बाजार मूल्य/उपभोक्ता मूल्य = कारक लागत + Tax – Subsidy

vFk'kkL= के क्षेत्र

- अर्थव्यवस्था के कुल पांच क्षेत्र माने जाते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले क्षेत्र मात्र तीन ही होते हैं ।

1. प्राथमिक क्षेत्र :-

- इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से आर्थिक कार्य किये जाते हैं सामान्यतः इस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है । जैसे- कृषि, वन, मछली पालन आदि
- इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ।

2. द्वितीयक क्षेत्र :-

- निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन आदि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ मानी जाती है ।
- इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है ।
- खनन, उत्खनन, बिजली उत्पादन आदि भारत में द्वितीयक क्षेत्र में लिये जाते है ।

3. तृतीयक क्षेत्र :-

- इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ।
- इस क्षेत्र में केवल सेवाएं शामिल की जाती है । जैसे- डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए आदि ।

4. चतुर्थक क्षेत्र :-

- इस क्षेत्र में बौद्धिक सेवाएं शामिल की जाती है । जैसे- सांस्कृतिक सेवाएं, उच्च शिक्षा, अनुसंधान आदि ।

5. पंचम क्षेत्र :-

- उच्च स्तरीय राजनैतिक और आर्थिक निर्णय संबंधित सेवाएं इस क्षेत्र में शामिल की जाती है । जैसे- मंत्री, प्रधानमंत्री, कम्पनी के CEO आदि

क्षेत्र	GDP में योगदान	रोजगार में योगदान
कृषि	17%	50%
उद्योग	25%	25%
सेवा	58%	100%

बाजार आधारित मूल्य निर्धारण

1. **मांग का नियम** :- इस नियमानुसार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों और मांग में नकारात्मक/विपरीत संबंध होता है अर्थात दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमत बढने पर उनकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ जाती है ।

2. **पूर्ति का नियम** :- इस नियमानुसार वस्तुओं की कीमतों और उनकी आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है अर्थात दीर्घकाल में अधिक मूल्य पर अधिक आपूर्ति और कम मूल्य पर कम आपूर्ति होती है ।

- स्वतंत्र बाजार में मूल्य निर्धारण ऐसे बिन्दु पर होता है जहां उपभोक्ता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हों ।

- अल्पकाल में अत्यधिक मांग बढने पर वस्तुओं की कीमतें बढ जाती है ।
- इसी प्रकार अल्पकाल में अत्यधिक आपूर्ति होने पर कीमतों में गिरावट आती है ।

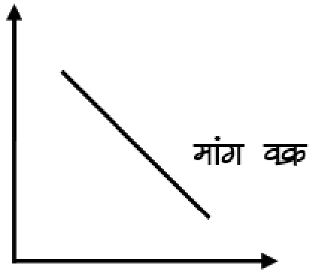

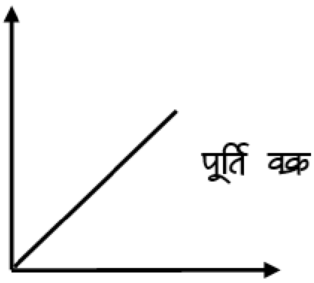

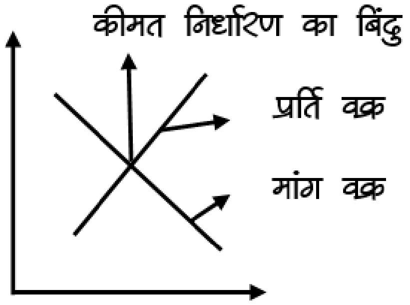

मांग व पूर्ति के नियम के अपवाद :-

(1) मूलभूत आवश्यकताएं- नमक, दवाइयां इत्यादि
(2) विलासिता की वस्तुएं- हीरा, सोना इत्यादि
(3) सामाजिक प्रतिष्ठा से जुडी वस्तुएं - क्लब की सदस्यता, लग्जरी कार आदि
उपरोक्त 2,3 को Vebles Goods के नाम से भी जाना जाता है।
(4) फैशन की वस्तुएं
(5) मादक पदार्थ
(6) निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं (Giffen Goods)

पूंजी बाजार

वित्तीय बाजार :-

- ऐसा बाजार जिसमें वित्तीय लेनदेन किये जाते है अर्थात ऐसा स्थान जहां पर एक व्यक्ति धन उधार लेने के लिए तथा दूसरा व्यक्ति निवेश करने के लिए आता है ।
- वित्तीय बाजारों को समय के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है ।

1. मुद्रा बाजार :-

- ऐसा वित्तीय बाजार जिसमें एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए वित्तीय लेन-देन होते है, मुद्रा बाजार कहलाता है । जैसे- Money at Call, Money at Short Notice, Commercial Paper, Treasury Bill etc

2. पूंजी बाजार :-

- ऐसा वित्तीय बाजार जिसमें लम्बी अवधि (1 वर्ष से अधिक) के वित्तीय लेनदेन होते है, पूंजी बाजार कहलाते है । जैसे-Equity Share (समता अंश), पूर्वाधिकार अंश, Debenture- ऋणपत्र, Bonds
- पूंजी बाजार दो प्रकार के होते है-
  (1) प्राथमिक बाजार :-
  - यह ऐसा पूंजी बाजार है जिसमें नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है । जैसे- IPO (Initial Public Offer), FPO (Follow on Public Offer/ Further Publilc Offer) etc

  (2) द्वितीयक बाजार :-
  - इस बाजार में प्राथमिक बाजार में जारी की गई प्रतिभूतियों का पुनः विक्रय किया जाता है । जैसे-BSE, NSE etc
  - द्वितीयक बाजार का सामान्यतः निर्धारित स्थान होता है जबकि प्राथमिक बाजार का कोई स्थान नहीं होता ।

IPO (Intial Public Offer) :-

- यदि कम्पनी द्वारा अपने जीवन में पहली बार अंश या ऋणपत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाये तो यह IPO कहलाता है ।
- IPO केवल सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा लाया जा सकता है ।

FPO (Follow on Public Offer) :-

- IPO लाने के बाद कम्पनी द्वारा जनता को अंश और ऋणपत्र खरीदने के लिए जनता को दिये आमंत्रण, FPO कहलाते है ।

अंश पूंजी / Share

- कम्पनी में स्वामीयों की पूंजी को अंश/शेयर पूंजी कहा जाता है ।
- लेनदेन की सुविधा के लिए अंश पूंजी को छोटे-छोटे टुकडों में बांटा जाता है ।
- अंश पूंजी का एक भाग एक अंश कहलाता है ।
- प्रत्येक अंशधारी कम्पनी का मालिक या स्वामी माना जाता है ।
- प्रत्येक अंशधारी को कम्पनी के लाभ मे हिस्सा लेने का अधिकार होता है इसे लाभांश कहते है ।

- अंश पूंजी दो प्रकार की होती है-

1. पूर्वाधिकार अंश/अधिमान अंश :-

- ऐसे अंशधारी जिन्हें निम्न दो पूर्वाधिकार हो पूर्वाधिकार अंश कहलाते है :-
  (1) चालू व्यवसाय के दौरान समता अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्ति अधिकार
  (2) व्यवसाय समापन के समय समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी का अधिकार

2. समता अंशधारी (सामान्य अंश धारी) :-

- ऐसा अंश जिसे उपरोक्त दोनों पूर्वाधिकार प्राप्त ना हो समता अंशधारी कहलाते है।
- अंशधारियों की सामान्य सभा में समता अंशधारी को मताधिकार प्राप्त होता है अतः यह निर्णय निर्माण में भागीदार होते है, इसलिए इन्हें वास्तविक स्वामी कहा जाता है।

शेयर बाजार में निवेशक :- निवेशक दो प्रकार के होते है-

1. वास्तविक निवेशक - यह अपनी बचत को लम्बी अवधि के लिए निवेश करते है।
2. सट्टेबाज -
   - यह अंश बाजार में आने वाले उतार-चढाव का लाभ उठाने के उद्देश्य से अल्पकालीन निवेश करते है।
   - सट्टेबाज दो प्रकार के होते है-
     (1) तेजड़िया - बाजार में तेजी की उम्मीद करते है।
     (2) मन्दड़िया - बाजार में मंदी की उम्मीद करते है।

शेयर बाजार में सौदों के प्रकार

1. Spot :- ऐसा सौदा जिसमें शेयर खरीदने तथा बेचने का समझौता तथा वास्तविक लेन-देन एक ही समय में किया जाये तो वह Spot कहलाता है। भारत में लेनदेन के दिन के अतिरिक्त दो दिन का समय दिया जाता है जिसे (T+2) नियम कहते है।

2. Forward :- भविष्य में लेनदेन करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाता है अर्थात समझौता तथा लेनदेन अलग-अलग दिन होते है।
   Forward की विशेषताएं :-
   - यह अनौपचारिक समझौते होते है।
   - इनका कोई मानक आकार नहीं होता है।
   - समझौता केवल निर्धारित तिथि पर पूरा किया जाता है यह समझौते Stock Exchange के बाहर भी किये जाते है।

3. Future :- भविष्य में लेनेदेन करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाता है अर्थात समझौता तथा लेन-देन अलग-अलग दिन होते है।
   Future की विशेषताएं :-
   - यह औपचारिक समझौता होता है।
   - इस समझौते का एक मानक आकार होता है।
   - यह Stock Exchange के माध्यम से किया जाता है।

- इसका निपटारा निर्धारित तिथि या कभी भी किया जा सकता है ।
- निर्धारित तिथि तक इसका लाभ व हानि को रोज ज्ञात किया जाता है ।
- इस प्रक्रिया को मार्क-टू-मार्केट कहा जाता है ।

4. Option :-

- भविष्य में लेनदेन करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में समझौता किया जाता है अर्थात समझौता तथा लेनदेन अलग-अलग दिन होते है ।
- Option में क्रेता को निर्धारित तिथि पर समझौता पूरा करने या ना करने का विकल्प दिया जाता है
- Option विक्रेता द्वारा बदले में प्रीमियम वसूल किया जाता है ।

नकद निपटारा :-

- Option व Future में निर्धारित तिथि को अंशों का क्रय-विक्रय किए बिना अनुमानित लाभ-हानि का नगद लेनेदेन नगद निपटारा कहलाता है ।
- वस्तु बाजार में इसकी अनुमति नहीं है ।

Short-Selling :-

- यदि वास्तव में अंश ना होते हुए भी अंशों का विक्रय किया जाये तो यह Short-Selling कहलाता है
- लेकिन विक्रय के बाद निपटारे के समय बाजार से शेयर खरीदकर दिये जाते है । यह अंश बाजार में गिरावट आने पर लाभ कमाने की प्रक्रिया है ।

Arbitrage

- Arbitrage से अभिप्राय जोखिम रहित लाभ से है । यदि एक प्रतिभूति एक समय में दो बाजारों में उपलब्ध हो और दोनों बाजारों की कीमतों में अन्तर हो तो सस्ते बाजार से खरीदकर महंगे बाजार में बेचना Arbitrage कहलाता है । जैसे- NSE से शेयर खरीदकर BSE में बेचना ।
- शेयर खरीदने बेचने में शेयर बाजार में खातों की आवश्यकता होती है।

1. Bank A/C :-

- यह सामान्य किसी बैंक में खुलवाया जा सकता है उदा.- बचत खाता, चालू खाता

2. Demat A/C :-

- प्राचीन समय में अंश कागज के प्रमाण-पत्र के रूप में जारी किये जाते थे यह अंशों का भौतिक स्वरूप कहलाता था ।
- कागज के प्रमाण-पत्र को समाप्त करके अंशों को डिजिटल स्वरूप में बदलना अभौतिकीकरण कहलाता है ।
- जिस खाते में अंशों को डिजिटल स्वरूप में रखा जाता है वह Demat A/C कहलाता है ।
- Demat A/C डिपोजटरी के माध्यम से खुलवाया जाता है ।
- भारत में दो डिपोजटरी कार्यरत है-

(a) NSDL – National Security Depository Limited संस्थापक– NSE (1996)
(b) CDSL – Central Depository Service Limited संस्थापक– BSE (1998)

3. <u>व्यापार खाता</u> :- यह खाता शेयर ब्रोकर के माध्यम से खुलवाया जाता है इसका उपयोग अंशों के क्रय-विक्रय के आदेश देने के लिए किया जाता है ।

Angel Investor :-

- यह व्यक्तिगत निवेशक होते है जो किसी व्यक्ति की प्रतिभा पर भरोसा करके व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध करवाते है ।
- आयकर अधिकारियों द्वारा Angel Investor से प्राप्त राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत टैक्स लगाया जाता है जिसे Angel Tax नाम से जाना जाता है । क्योंकि यह टैक्स सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के खिलाफ था । इसलिए सरकार द्वारा हाल ही में 25 करोड रूपये तक का Angel Investment; Tax से माफ किया है ।

वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund) :-

- यह संस्थागत निवेशक होते है । यह तकनीकी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक पूंजी (Seed Money) उपलब्ध करवाते है ।
- यह निवेश से पहले विशेषज्ञ टीम की सहायता से परियोजना का गहन अध्ययन करते है और लाभ के बारे में आश्वस्त होने पर ही निवेश करते है ।
- यह निवेश के बदले में कम्पनी में हिस्सेदारी की मांग करते है ।

<u>HUNDI</u> :- प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के स्थानान्तरण के लिए वर्तमान चैक के समान प्रतिभूति का उपयोग किया जाता था जिसे HUNDI कहते है ।

<u>ऋणपत्र</u> :-

- कम्पनी द्वारा आम निवेशकों से छोटी-छोटी राशि में उधार लिया जाता है और उसके बदले में ऋण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसे ऋणपत्र कहते है ।
- यह दीर्घकालीन ऋण के लिए काम में लिया जाता है ।

Commercial Paper :-

- बडी कम्पनियों द्वारा अल्पकालीन ऋण के लिए लायी गयी प्रतिभूति ।
- यह मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है ।

<u>ट्रेजरी बिल</u> :-

- सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण के लिए काम में ली गई प्रतिभूति
- यह भी मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है ।
- यह केवल केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकते है ।
- इसके प्रचलित रूप निम्न है-

  (1) T – 91 (2) T – 182 (3) T - 364
- अधिकतम 364 दिन होता है ।

Bond :-

- यदि सरकार द्वारा दीर्घकालीन ऋण के लिए ऋणपत्र के समान प्रतिभूति जारी की जाती है तो वह Bond कहलाती है ।
- Bond सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा भी जारी किया जा सकता है ।

GILT-EDGE :- सरकार की प्रतिभूतियाँ निवेश के लिए सुरक्षित मानी जाती है । ऐसी प्रतिभूतियों को GILT-EDGE नाम से जाना जाता है ।

म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) :-

- यह एक प्रकार का सामूहिक निवेश है । बहुत सारे निवेशकों द्वारा निवेश करके बडी मात्रा में धनराशि एकत्रित की जाती है ।
- इस धनराशि को विशेषज्ञों द्वारा निवेश किया जाता है । निवेश पर प्राप्त आय में से म्यूचुअल फंड के खर्चे घटाने के बाद शेष राशि निवेशकों में लाभांश के रूप में बांट दी जाती है ।
- म्यूचुअल फंड में निवेशकों को यूनिट धारक के नाम से जाना जाता है ।

SIP (Systematic Investment Plan) :- म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम जिसमें लम्बी अवधि तक लगातार निवेश किया जाता है ।

ULIP (Unit Linked Insurance Plan) :- यदि बीमा Plan में प्रीमियम की राशि म्यूचुअल फंड के समान निवेश की जायें तो वह ULIP कहलाता है ।

UNDER-WRITER :-

- यदि IPO & FPO में कम्पनी द्वारा जारी किये जाने वाले सभी अंश ना बिक पायें तो IPO & FPO विफल माना जाता है और सभी निवेशकों की आवेदन राशि लौटा दी जाती है ।
- Under-Writer एक ऐसा व्यक्ति व संस्था होता है जो IPO & FPO में कम्पनी के सभी अंश बिकवाने तथा ना बिकने पर स्वयं खरीदने की गारंटी देता है ।

Green Shoe Option :- IPO & FPO में जारी किये जाने वाले अंशों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है । यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त हो तो Green Shoe Option कम्पनी को अतिरिक्त आवेदकों को अंश आवंटित करने का विकल्प प्रदान करता है ।

Book Building :- IPO & FPO में यदि कम्पनी अंशों का मूल्य घोषित करने के स्थान पर अंशों का न्यूनतम या अधिकतम मूल्य घोषित करें और निवेशकों में बोली व नीलामी व सर्वे के माध्यम से अंशों का बाजार मूल्य ज्ञात करें तो यह प्रक्रिया Book Building कहलाती है

Stock Exchange

- यह प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाजार है ।
- भारत में क्षेत्रीय Stock Exchange के अतिरिक्त दो राष्ट्रीय Stock Exchange कार्यरत है ।

BSE (Bombay Stock Exchange) :-

- इसकी स्थापना 1875 में की गई ।
- यह एशिया का सबसे पुराना Stock Exchange है ।
- 2005 ई. में इसे कम्पनी में परिवर्तित किया गया ।
- कारोबार की दृष्टि से यह भारत में दूसरे स्थान पर होता है ।
- सौदों की संख्या के आधार पर यह भारत में पहले स्थान पर आता है ।
- बाजार पूंजीकरण के आधार पर यह भारत का सबसे बडा Exchange है ।
- यह आम निवेशकों में अधिक लोकप्रिय है ।
- बाजार पूंजीकरण = अंशों की संख्या × अंशों का बाजार मूल्य
- इसका मुख्य सूचकांक/ Sensex = संवेदी सूचकांक कहलाता है ।

सूचकांक (SENSEX) :-

- यह बाजार पूंजीकरण के आधार पर 30 सबसे बडी कम्पनियों के अंशों के प्रदर्शन का भारित औसत है ।
- इसके अतिरिक्त BSE निम्न सूचकांक भी जारी करती है ।
  Ex- BSE 100, BSE 200 (Dollex), Green Ex (20), Bankex (12)

NSE (National Stock Exchange) :-

- इसकी स्थापना 1992 ई. में हुई व इसका मुख्यालय मुम्बई में है ।
- इसका मुख्य संस्थापक IDBI था ।
- NSE के 20% अंश न्यूयार्क Stock Exchange के पास है ।
- यह प्रारम्भ से ही पूर्णतः इलेक्ट्रानिक Exchange था ।
- कारोबार (टर्न-ओवर) की दृष्टि से भारत का सबसे बडा Exchange है ।
- जबकि सौदों की संख्या और बाजार पूंजीकरण में यह दूसरे स्थान पर आता है ।
- यह संस्थागत निवेशकों में अधिक लोकप्रिय है ।
- इसका मुख्य सूचकांक NIFTY (National Index of Fifty) है ।
- यह 50 कम्पनियों के भारित औसत पर आधारित है ।
- NIFTY ज्ञात करने करने का सूत्र विदेशी संस्था Standard & Poor द्वारा दिया गया ।
- NSE का other सूचकांक जूनियर NIFTY कहलाता है ।

राष्ट्रीय आय

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है।
- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रीय आय के लिए आंकडो का संकलन NSSO & CSO द्वारा किया जाता है।
- यह दोनों संस्थाएँ MOSPI के अन्तर्गत कार्य करती है।

(1)	MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)
(2)	NSSO = National Sample Survey Office/Organization (राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन)
(3)	CSO = Central Statistics Office (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन)

- NSSO ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के आंकडे एकत्रित करता है।
- CSO संगठित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, शहरी क्षेत्र आदि के आंकडे एकत्रित करता है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त कर विभाग के आंकडे जैसे- GST के आंकडे भी लिये जाते है।
- कम्पनियों के आंकडे MCA-21 वेबसाइट से लिये जाते है।
- हाल ही में NSSO द्वारा MCA-21 के आंकडों को अविश्वसनीय घोषित किया क्योंकि MCA-21 पर बहुत सारी कम्पनियां Shell Company/Paper Company है।
- Paper कम्पनी से अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है जिन्हें कर चोरी व काला धन आदि के उद्देश्य से बनाया जाता है। उनके द्वारा कागजों में दिखाया गया व्यवसाय झूठा होता है। इनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त विनियामक संस्थाओं जैसे- RBI, IRDA, SEBI आदि के आंकडों का भी प्रयोग किया जाता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है-
  (1) आय विधि
  (2) व्यय विधि
  (3) उत्पादन विधि

- भारत में मिश्रित विधि का उपयोग किया जाता है।
- कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है।
- सेवा क्षेत्र के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है।
- भारत व्यय विधि का उपयोग नहीं करता है।
- राष्ट्रीय आय की गणना चार मूल्यों पर आधारित होती है।

(1) कारक लागत

(2) <u>बाजार मूल्य</u>- वह मूल्य जिस पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा वस्तुएँ खरीदी जाती है। इसे वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है।

(3) <u>आधार मूल्य</u>-
  - राष्ट्रीय आय की तुलना के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है।
  - भारत में 2011-12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है।
  - किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य आधार मूल्य कहलाता है।

(4) स्थिर मूल्य-
- यदि बाजार मूल्य में से मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाये तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है ।
- राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित है- GDP, GNP, NDP, NNP

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) :- एक वित्त में किसी देश के निवासियों द्वारा देश की आर्थिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है ।

वित्त वर्ष :-
- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूंढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया

(1) बेल्बी आयोग
(2) L. K. JHA समिति
(3) दार्निश वाचा समिति
(4) शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)

आर्थिक सीमा :-
- आर्थिक सीमा से अभिप्राय भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से है ।
- भारत की भौगोलिक सीमा से 200 NM सीमा तक का महासागरीय जल भारत का अनन्य क्षेत्र माना जाता है । 1 NM (Notical Mile) – 1.8 km

निवासी :- भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार एक वित्त वर्ष में 6 महीने से अधिक भारत में रहने वाला व्यक्ति उस वर्ष के लिए भारत का निवासी माना जाएगा ।

अंतिम वस्तु एवं सेवा :- उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तुएं दो प्रकार की होती है ।
(1) मध्यस्थ वस्तुएं :- ऐसी वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती है, मध्यस्थ वस्तुएं कहलाती है। अर्थात यह वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग में नहीं ली जाती । जैसे- कार का इंजन
(2) अंतिम वस्तुएं :- ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है अर्थात इनमें उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है और उत्पादन संभव नहीं होता है । जैसे- कार

- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को छोड दिया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है ।
- भारत की GDP गणना अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे GVA (सकल मूल्य संवर्द्धन) आधारित बनाया गया ।

  (1) GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit

  (2) GVA_{bp} = GVA_{fc}+ उत्पादन कर – उत्पादन Subsidy

  (3) GDP_{mp} = GVA_{bp}+ उत्पाद कर – उत्पाद Subsidy
- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते है, आधार मूल्य कहलाता है ।

<u>उत्पादन कर</u> :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कर । जैसे- कच्चे माल पर लगने वाला कर
<u>उत्पादन Subsidy</u> :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली Subsidy । जैसे- स्वदेशी कच्चे माल पर Subsidy
<u>उत्पाद कर</u> :- अंतिम उत्पाद कर प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला कर । जैसे- Excise Duty, GST etc. यह कर अंतिम उपभोक्ता से वसूला जाता है जबकि उत्पादन कर उत्पादक से लिया जाता है ।
<u>उत्पाद Subsidy</u> :- अंतिम उत्पाद पर उपभोक्ता को दी जाने वाली Subsidy जैसे- Subsidy on Car

<u>शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)</u> :-

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से मूल्य ह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है।
- विभिन्न देशों में मूल्य ह्रास गणना अलग-अलग विधियों से की जाती है । इसलिए NDP का आधार प्रत्येक देश में समान नहीं होता ।
- इस कारण NDP का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

  $NDP_{mp} = GDP_{mp} - Dep.$ (मूल्य ह्रास)
- <u>मूल्य ह्रास</u> :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है ।

<u>**सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)**</u> :- एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GNP कहलाता है ।

(1) $GNP_{mp} = GDP_{mp} \pm$ Net factor Income from abroad (NFIFA)
(2) NFIFA = Income of Indian Citizen outside India – Income earned by foreigner in India

<u>शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)</u> :-

- इसकी गणना के लिए GNP में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है ।
- भारत में कारक लागत पर NNP को राष्ट्रीय आय माना जाता है ।
- बाजार मूल्य/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) कहा जाता है ।
- $NNP_{mp} = GNP_{mp} -$ Dep.(मूल्य ह्रास)
- $NNP_{fc} = NNP_{mp} -$ अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} / \frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp} -$ मुद्रास्फीति (CP = -स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक GDP भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर GDP को Nominal GDP भी कहा जाता है ।
- GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{\text{GDPmp}}{\text{GDPcp}}$

मुद्रास्फीति (Inflation)

- किसी देश/अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढना मुद्रास्फीति कहलाता है ।
- मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है अर्थात महंगाई का बढना या रूपये के मूल्य में गिरावट मुद्रास्फीति कहलाता है ।

मुद्रा अवस्फीति (Deflation):–

- यदि अर्थव्यवस्था या देश में वस्तु या सेवाओं की कीमतें लगातार कम हो रही हो तो वह मुद्रा अवस्फीति कहलाती है ।
- मुद्रा अवस्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ जाती है अर्थात वस्तुएं सस्ती होना या रूपये का मूल्य बढना मुद्रा अवस्फीति कहलाता है ।

Growth Flation :–

- किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुद्रास्फीति को आवश्यक/महत्वपूर्ण माना जाता है।
- महंगाई की अत्यधिक दर दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालती है ।
- मुद्रास्फीति की वह दर जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी हो ।
- मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढावा मिलता है ।
- नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति की दर हासिल करना प्रत्येक देश का लक्ष्य होता है इसलिए इसे Targetting Inflation भी कहा जाता है ।
- विकसित देशों के लिए 1 - 2% तथा विकासशील देशों के लिए 4 - 5% मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है ।

Dis-Inflation :– यदि समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ रही है । लेकिन मुद्रास्फीति की दर/गति कम हो रही हो तो यह Dis-inflation की परिस्थिति कहलाती है । अर्थात ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रास्फीति घटती हुई दर से बढती है ।

उदा. –

Year	Price	Inflation Rate (महंगाई दर)
2015	500/-	$\frac{100}{500} \times 100 = 20\ \%$
2016	600/-	$\frac{100}{600} \times 100 = 16.67\ \%$
2017	700/-	$\frac{100}{700} \times 100 = 14\ \%$
2018	800/-	$\frac{100}{800} \times 100 = 12.5\ \%$
2019	900/-	$\frac{100}{900} \times 100$

Galloping/Runaway/Hyper-Inflation :– ऐसी परिस्थिति जिसमें महंगाई बढने के साथ–साथ मुद्रास्फीति बढने की दर या गति भी बढ जाये अर्थात मुद्रास्फीति बढती हुई दर से बढती है

उदा. –

Year	Price	Inflation Rate (महंगाई दर)
2015	100/-	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\ \%$
2016	200/-	$\frac{300}{200} \times 100 = 150\ \%$
2017	500/-	$\frac{1000}{500} \times 100 = 200\ \%$
2018	1500/-	$\frac{3500}{1500} \times 100 = 230\ \%$
2019	5000/-	

घातक परिस्थिति

Creeping Inflation :- यदि मुद्रास्फीति बढने की दर बहुत कम हो या बहुत धीमी हो तो वह Creeping Inflation कहलाती है। इस परिस्थिति में सामान्यतः मुद्रास्फीति की दर 1 अंक तक ही रहती है।

Stag Flation :-

- यदि किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों समस्याएँ विद्यमान हो तो यह Stag Flation कहलाती है।
- यह सरकार एवं केन्द्रीय बैंक के लिए असमंजस की स्थिति होती है। यदि RBI द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज की दर बढाई जाती है तो इससे निवेश और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, जिससे बेरोजगारी और बढ जाती है।

फिलीप का सिद्धान्त :- फिलीप के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में अल्पकाल में नकारात्मक या विपरीत संबंध होता है अर्थात यदि मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ जाती है और मुद्रास्फीति बढने से बेरोजगारी कम हो जाती है।

लागत जनित मुद्रास्फीति (Cost Push Inflation) :- यदि उत्पादन के कारकों की लागत बढने के कारण वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ जायेगी तो यह लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे- कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी दर में वृद्धि आदि

मांग जनित मुद्रास्फीति (Demand Pull Inflation) :- यदि वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ जाने के कारण वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ जाये तो यह मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है।

मांग बढने के कारण :-

(1) जनसंख्या में वृद्धि
(2) व्यक्तिगत आय में वृद्धि
(3) ब्याज की दरों में कमी आना
(4) राजकोषीय नीति में परिवर्तन
(5) विदेशी निवेश में वृद्धि
(6) काले धन में वृद्धि

संरचनात्मक मुद्रास्फीति :-

- यदि वस्तुओं की मांग और लागत में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ जायें तो वह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है।
- आपूर्ति बाधित होने का कारण उत्पादक या विक्रेता/आपूर्तिकर्ता संस्थान में संरचनात्मक कमजोरी को माना जाता है।
- जैसे- 1. समय पर कच्चा माल उपलब्ध न होना।
  2. उत्पादन प्रक्रिया में विलम्ब।
  3. यातायात साधनों की अनुचित व्यवस्था आदि
- इसे Bottle Neck मुद्रास्फीति भी कहा जाता है।